आकाशवाणी केन्द्र शिमला

21.10.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार

- केंद्र की उड़ान योजना के 8 साल पूरे–प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा–योजना से भारत के विमानन क्षेत्र के परिदृश्य में आया बदलाव।
- मुख्यमंत्री की आउट सोर्स, आंगनबाड़ी, आशा व मल्टी टास्क वर्करों को 28 अक्तूबर को वेतन देने की घोषणा।
- नगर निगम शिमला कोर्ट के आदेशों के बाद संजौली स्थित मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम आज से आरंभ।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा–व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था का पतन कर रही है प्रदेश सरकार।

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि सरकार की (उड़े देश का आम नागरिक) उड़ान योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र को बदल दिया है। उड़ान योजना की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इस योजना ने हवाई अड्डों और हवाई मार्गों की संख्या में वृद्धि के साथ करोड़ों लोगों के लिए उड़ान तक पहुंच सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि साथ ही, इस योजना का व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरकार लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा पर ध्यान केंद्रित करते हुए विमानन क्षेत्र को मजबूत करना जारी रखेगी।

उड़ान

इस बीच कुल्लू जिला के भुंतर स्थित एयरपोर्ट के लिए उड़ान योजना के तहत हवाई उड़ानों में हुई वृद्धि से कुल्लू घाटी में जहां पर्यटकों की आमद बढ़ी है वहीं स्थानीय लोगों के लिए भी हवाई यात्रा पहले से अधिक सस्ती और सुलभ हुई है। इससे पहले इस हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए ही हवाई सेवा उपलब्ध थी। लेकिन अब अमृतसर, देहरादून और जयपुर के लिए भी सीधी उड़ाने हो रही हैं। ऐसे में जो लोग सड़क मार्ग से यात्रा नहीं कर पाते थे वे अब आसानी से कुल्लू घाटी घुमने पहुंच रहे हैं। भुंतर एयरपोर्ट से देहरादून और जयपुर के लिए हवाई यात्रा का किराया महज 25 सौ रूपए है।

आउटसोर्स.

प्रदेश सरकार ने दिपावली के पर्व को देखते हुए आउट सोर्स, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और मल्टी टाक्स वर्करों को भी 28 अक्तूबर को वेतन देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ये घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 85 हजार करोड़ रूपए का कर्ज छोड़ कर गई और अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आर्थिक संकट को लेकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने संजौली में मस्ज़िद कमेटी द्वारा मस्ज़िद में हुए अवैध निर्माण को स्वंय तोड़ने की शुरूआत करने पर कहा कि हिमाचल देश का ऐसा

पहला राज्य है जिसने आपसी भाईचारे की मिशाल पेश की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष खुद मस्ज़िद तोड़ने के लिए आगे आया है जो सराहनीय कदम है।

<u>सक्षम बच्चे</u>

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के उप नगर ढली में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान के लिए नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। 8 करोड़ 28 लाख रूपए की लागत से बने इस भवन में 32 आधुनिक सुविधाएं और आवासीय कमरों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इन सुविधाओं में 12वीं कक्षा तक की निशुल्क शिक्षा के अलावा हस्तशिल्प, बेकरी, कम्प्यूटर कौशल बागवानी जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विशेष रूप से सक्षम बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली औपचारिक और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

<u>मुख्यमंत्री</u>

इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में प्रदेश पुलिस के साईबर विंग के सी.वाई. स्टेशन का शुभारम्भ भी किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ये केंद्र पूरे सप्ताह और चौबिस घंटे काम कर साईबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी साईबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों को टॉल फ्री नम्बर 1 9 3 0 पर दर्ज करवा सकते हैं उन्होंने कहा कि इस स्टेशन पर लोग आर्थिक अपराध से जुड़ी कोई भी शिकायत रियल टाईम में दर्ज करवा सकेंगे।

<u>मस्जिद</u>

प्रदेश की राजधानी शिमला के उप–नगर संजौली स्थित मस्ज़िद विवाद अब सुलझता नजर आ रहा है। इस मस्जिद में बनी 3 अवैध मंजिलों को गिराने के नगर निगम शिमला कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद कमेटी ने स्वंय पहल की है और इस पर आज से काम भी आरंभ हो गया है

नगर निगम शिमला कोर्ट के आदेशों के बाद संजौली स्थित मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम आज से आरम्भ हो गया। <u>मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष लतीफ मोहम्मद की देखरेख में हो रहा है। मोहम्मद लतीफ ने बताया कि मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए अभी तक पूरे पैसे का इंतजाम नहीं हुआ है। इसके बावजूद तोड़ने का काम आरम्भ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए काफी अधिक पैसे की जरूरत है। इस कारण इस कार्य में तीन से चार माह का समय लग सकता है। इस बीच शहरी विकास व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मस्जिद का अवैध हिस्सा कानूनी प्रक्रिया के तहत तोड़ा जा रहा है।</u>

<u>नगर निगम कोर्ट ने 5 अक्तूबर को मस्जिद की अवैध रूप से बनी तीन मंजिलों को तोड़ने का आदेश दिया था। इस कार्य के लिए निगम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को दो महीने का समय दिया है। बाद में अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से अनुमति मांगी थी जो अब मिल गई है।</u>

<u>हाईकोर्ट</u>

इस बीच प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को संजौली मस्जिद के पूरे ढांचे की वैधता पर अंतिम फैसला 8 सप्ताह के भीतर करने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले के जल्द निपटारे के लिए संजौली के स्थानीय निवासियों की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को मस्जिद से जुड़ी वर्ष 2010 की शिकायत का निपटारा करने के आदेश दिए हैं। इस शिकायत में एम सी शिमला स्वयं शिकायतकर्ता है।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था का पतन कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने किए गए सभी गलत कामों को न्यायोचित ठहराने के लिए पूर्व सरकार पर दोषारोपण करने से बाज आएं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अब हिमाचल को बेचने की हिम्मत आ गई है और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की जमीन बेचने के लिए हो रहे प्रयास इसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों के बैग पर भी एचआरटीसी की बसों में किराया लगा दिया है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस की झूठी गारंटियां अब उसके गले की फांस बन गई हैं।

विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण विभाग और सतलुज जल विद्युत निगम के बीच आज सुन्नी–लूहरी सड़क के विस्तारीकरण की परियोजना को लेकर एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया। एस जेवीएन इस सड़क का घरट नाला खैरा से ढली–देवीधार तक विस्तारीकरण करेगा। इस कार्य पर 70 करोड़ रूपए खर्च होंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मौके पर कहा कि इस समझौते से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे।